

अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक मृत
गोंदिया - बिर सी निवासी राजेश श्रीराम कावले (30) बिरसी से तिरोड़ा रास्ते पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास के खेत में धान की रोपाई के लिए गया था। लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई।



साप्ताहिक

बुलंदगोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : अभिषेक चौहान | संपादक : नवीन अग्रवाल

E-mail : bulandgondia@gmail.com | E-paper : bulandgondia.net | Office Contact No. : 7670079009 | RNI NO. MAH-HIN-2020/84319



वर्ष : 5 | अंक : 28

गोंदिया : गुरुवार, दि. 20 फरवरी से 26 फरवरी 2025

पृष्ठ : 4 | मूल्य : ₹. 5

आमजन तक पहुंचाएं योजनाओं की जानकारी शालेय शिक्षा व खनन विभाग की समीक्षा में राज्यमंत्री डा. भोयर ने दिए निर्देश

बुलंद-गोंदिया-सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना तथा जनोन्मुखी कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना प्रशासन व संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होने के कारण शालेय शिक्षा, सहकारिता व खनन विभाग कुशलता से कार्य करें। ऐसे निर्देश गृह (ग्रामीण), गृह निर्माण, शालेय शिक्षा, सहकारिता व खनन विभाग के राज्यमंत्री डा. पंकज भोयर ने जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में शालेय शिक्षा, सहकारिता व खनन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल रहगुडाले, सभापति लक्ष्मण भगत, जिलाधीश प्रजीत नायर, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, जपि सीईओ मुरगानंदम प्रमुखता से उपस्थित थे। राज्यमंत्री डा. भोयर ने कहा कि शालेय शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री, मेरी शाला-सुंदर शाला पहल का प्रभावी व सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए, गोंदिया जिले में %पीएम श्री शाला% योजना के अंतर्गत 20 स्कूल हैं और मानव संसाधन विकास पर व्यय किया गया है। इससे स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने शिक्षा विभाग को 20 स्कूलों का विकासत्मक



ऑडिट कराने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की संकल्पना के अनुसार %पीएम श्री शाला% पहल की तर्ज पर %सीएम श्री शाला% पहल शुरू की जानी चाहिए, अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई %आदर्श विद्यालय% पहल राज्य के 478 विद्यालयों में क्रियान्वित की जा रही है। गोंदिया जिले में कुल 1642 स्कूल हैं और %आदर्श स्कूल% पहल के तहत जिले में 9 छोटे और 9 बड़े स्कूलों का निर्माण किया गया है, उन्होंने सुझाव दिया कि इन स्कूलों का भी विकासत्मक ऑडिट कराया जाना चाहिए, गोंदिया जिले में 290 विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियां और 39 आदिवासी सहकारी समितियां हैं। जिले में ऐसी कुल 329 सहकारी समितियां हैं, इनमें से 121 सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है।

इसके तहत 12 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि इन सभी गतिविधियों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए, गोंदिया जिले में कुल 33 रेत के घाट हैं, जिला प्रशासन रेत चोरी से संबंधित अवैध उत्खनन व परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है। फसलों की क्षति का सर्वेक्षण जल्द कराएँ उन्होंने कहा कि पीडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में जिले के नागरिकों में प्रभावी जनजागृति की जाए, वन विभाग जंगली जानवरों द्वारा कृषि फसलों को पहुंचाई गई क्षति का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराएँ और मुआवजा प्रदान करें, इस अवसर पर जिलाधीश प्रजीत नायर ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों, जिला परिषद शिक्षक स्थिति, विद्यार्थी आईडी स्थिति, स्कूलों में उपलब्ध भौतिक

सुविधाएं, पीएम श्री योजना, दसरमुक्त शनिवार, अटल खेल और सांस्कृतिक महोत्सव, डा. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श स्कूल निर्माण, जिला नियोजन समिति के माध्यम से जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल का विकास, प्रथम संस्था के सहयोग से जिले के स्कूलों गुणवत्तापूर्ण विकास, जिले में संचालित प्रमुख खनिज और गैर खनिज खनन बेल्ट, अवैध खनन और परिवहन मामले, जिला खनिज प्रतिष्ठान की वर्तमान स्थिति, जिले में रेत/रेत डिपो की वर्तमान स्थिति आदि पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में शिक्षाधिकारी (माध्यमिक) डा. महेंद्र गजभिये, शिक्षाधिकारी (प्राथमिक) सुचीर महामुनि, जिला उप निबंधक प्रशांत सोनारकर, जिला खनिज अधिकारी रवींद्र मारबते सहित विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कचारगड यात्रा के दौरान स्वास्थ्य स्टाल का जिलाधिकारी प्रजीत नायर ने किया दौरा

बुलंद गोंदिया। कचारगड यात्रा 10 से 14 फरवरी तक चली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर सालेकसा तहसील में स्थित कचारगड को आदिवासी समुदाय की जन्मभूमि माना जाता है और पूरा आदिवासी समुदाय यहां श्रद्धा के साथ आता है और श्रद्धांजलि देता है। हर साल माघी पूर्णिमा के अवसर पर लगभग पांच से छह लाख श्रद्धालु अपने पूर्वजोंको नमन करने यहां आते हैं। सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से उन लाखों श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य प्रशासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरेकसा के माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यात्रा के सभी पांच दिनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरेकसा के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदर्शनी और शिविरों का आयोजन किया गया है। 12 फरवरी को जिलाधिकारी प्रजीत नायर और पुलिस अधीक्षक गोरख भांबरे ने कचारगड यात्रा और कोपर लिंगो माँ काली कंकाली देवस्थान का दौरा किया। उस समय उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का दौरा किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उस समय उनके साथ तहसीलदार नरसह्या कुंडा गोरले, पिपरिया क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य गीताताई लिलहारे और सालेकसा



पंचायत समिति सदस्य सुनीताताई राउत मौजूद थे। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से छोटी-मोटी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं, जल शुद्धिकरण, जल स्रोतों के कीटाणुशोधन का प्रचार-प्रसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितिन वानखेड़े के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरेकसा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारस गिरी ने यात्रा के दौरान पांचों दिनों के लिए चिकित्सा दल के कार्य की योजना बनाई है, दवा भंडार, स्वास्थ्य कार्यक्रम व योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की है तथा स्टाल लगाया है। यात्रा के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभाकर डोंगरवार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता शिरसागर, प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी उन्नति उपलवार सहित अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य संस्था की आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

युवती की गला घोट हत्या कर जलने वाले आरोपी को दे फांसी सकल समाज समिति ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे की मांग

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के अंतर्गत 18 वर्षीय युवती की हत्या करने के बाद जलने वाले आरोपी को फांसी देने के लिए सकल हिंदू समाज ने 13 फरवरी 2025 गुरुवार को मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की।



गोरेगांव तहसील में काम करने वाली 18 वर्षीय युवती को प्रेमला में फंसा कर उसका शारीरिक शोषण कर गर्भवती बनाने के पश्चात उसकी दुष्टता से गला घोट जलाकर हत्या कर सबूत मिटाने का मामला सामने आने पर तथा एक समाज विशेष के आरोपों का नाम इस हत्याकांड में सामने आने पर इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा जल्द से जल्द इसका खुलासा कर आरोपी को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस प्रकार का मामला सामने आने पर हिंदूवादी संगठनों में इसे लेकर आक्रोश निर्माण हो रहा है तथा आरोपी के खिलाफ लगाई गई विभिन्न धाराओं की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। आरोपी के खिलाफ मामला फास्ट ट्रैक चलने वह उसे फांसी की सजा देने के लिए देने की मांग के लिए सकल हिंदू समाज समिति द्वारा 13 फरवरी को दोपहर 1:00 बजे शहर के नेहरू प्रतिमा परिसर में जमा होकर वहां से एक मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन देकर मांग की जिसमें विभिन्न मांगों में लव जिहाद के आरोपों पर लगाई गई धाराओं की जानकारी सार्वजनिक करें, अपराधी व उसके परिवार के बैंकग्रांड की जांच हो, मृतका गर्भवती थी इसलिए आरोपी पर भ्रूण हत्या का भी मामला दर्ज हो संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए सभी परिवार को मिलने वाली सभी प्रकार की शासकीय सुविधाओं का लाभ तत्काल रोका जाए। परिवार के सदस्य दूसरे राज्य से गोंदिया

में आकर रह रहे इस मामले की जांच सीबीआई से की जाए। इस हत्याकांड में परिवार के अन्य लोग सहयोगी होने की संभावना को देखते हुए निष्पक्ष जांच की जाए अवैध ईट भट्टे पर मामला दर्ज हो। पीड़िता के परिजनों या गवाहों पर दबाव बनाया जा सकता है इसलिए आरोपी के परिवार को हिरासत में लिया जाए। आरोपी मृतका का गत 3 वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा था तथा हत्या के समय उसकी आयु 18 वर्ष थी जिसे वह नाबालिक के साथ शोषण कर रहा था जिसमें उसके खिलाफ पारको के तहत भी मामला दर्ज हो। इन सभी मांगों का ज्ञापन सकल समाज समिति के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा जिला अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को देकर आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द जांच पूर्ण कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में मामला चलाकर फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है।

महाराष्ट्र में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में समीक्षा सभा

बुलंद गोंदिया (मुंबई)- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा सभा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस उपस्थित थे। बैठक में राज्य में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नये प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सभा में केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के नागरिकों को तेज और पारदर्शी न्याय प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपराधों का पंजीकरण आवश्यक है तथा एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नए आपराधिक कानूनों की तर्ज पर महाराष्ट्र में एक आदर्श अभियोजन निदेशालय प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।



इसने 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि दर हासिल करने के प्रयास करने का भी निर्देश दिया। पुलिस, सरकारी अभियोजकों और न्यायपालिका को समन्वय करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अपराधियों को यथाशीघ्र सजा मिले गृह मंत्री ने कहा कि संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ हिंसा की घटनाओं की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा, जेलों, सरकारी अस्पतालों, बैंकों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र को सीसीटीएनएस 2.0 और आईसीजेएस 2.0 प्रणाली अपनाने की सलाह दी और सुझाव दिया कि दो अलग-अलग राज्यों के

बीच एफआईआर के हस्तांतरण की सुविधा के लिए सीसीटीएनएस प्रणाली विकसित की जानी चाहिए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य के पुलिस थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की भी आवश्यकता है गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक पुलिस उप-मंडल में फॉरेंसिक विज्ञान मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञों की शीघ्र भर्ती की जानी चाहिए। इसके लिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को राष्ट्रीय स्थापित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएफआईएस) से जोड़ने का भी निर्देश दिया। इसने नए आपराधिक कानून के तहत अपराधियों से जब्त की गई संपत्ति को उनके मूल मालिकों को तुरंत वापस करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री ने पुलिस स्टेशनों के सौंदर्यकरण और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की हर पखवाड़े समीक्षा करनी चाहिए, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित

बुलंद गोंदिया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हरित ऊर्जा से चलने वाली पर्यावरण अनुकूल मोबाइल दुकानें (ई-वाहनों पर मोबाइल दुकानें) निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास महामंडल, मर्यादा द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत मुंबई स्तर से हो रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक



पुनर्वास करना। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामान्य लोगों की तरह अपने परिवार के साथ रहने में सक्षम बनाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन <https://register.mshfdc.co.in> लिंक पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस लिंक के माध्यम से दिव्यांगजन 10 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9090118218 या हेल्पलाइन ईमेल- evehicle.mshfdc@gmail.com पर संपर्क करें।

पिछड़े वर्ग के छात्र जाति दावे सत्यापन के संबंध में विशेष अभियान

बुलंद गोंदिया। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशानुसार क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुरूप उक्त अवधि में जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति गोंदिया के अंतर्गत सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय में प्रवेशित सभी पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपना जाति दावा सत्यापन प्रस्ताव समिति के समक्ष जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करें

तथा उसकी एक प्रति आवश्यक साक्ष्य के साथ जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, सामाजिक न्याय भवन, जिला कलेक्टर कार्यालय के पीछे, गोंदिया में यथाशीघ्र जमा करें। साथ ही, जिन आवेदकों ने अपने जाति दावा सत्यापन प्रस्ताव समिति कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन जिनके जाति दावा सत्यापन प्रस्ताव त्रुटि सुधार हेतु कार्यालय में लंबित हैं, वे समिति कार्यालय में आकर तुरंत त्रुटि सुधार कराएं। यह जानकारी गोंदिया के उपायुक्त एवं जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सदस्य ने दी है।

संपादनकिय

प्रशासन के कांटे

कुछ ही दिनों में दो अधिकारी रिश्त के आरोप में अपना दायित्व भ्रष्ट करने की सुविधियों में हैं। कुल्लू में आबकारी एवं कराधान और परागपुर में खंड विकास अधिकारी लगभग एक जैसे आचरण की बदौलत पकड़े गए। इससे महत्वपूर्ण यह कि किसी ने हिम्मत दिखाते हुए 'प्रशासन के ये कांटे' बाहर निकाले हैं। इनका जुर्म इनकी पद्धति और पद का प्रभाव है। जाहिर है हिमाचल की नाक ऐसे कारनामों में धंसी है, फिर भी भ्रष्टाचार की अपनी सक्रियता है जो राज्य की निष्पक्ष कार्यप्रणाली को हमेशा आँधे में डुबोती रहती है। एक तथ्यशुदा सहमति के तहत कुछ महकमों के अहम पद नवाजे जाते हैं और काम करने और करवाने की खुराक बन चुका है भ्रष्टाचार। हेरानी यह कि सरकारी पैसे को भी दो एजेंसियाँ बिना रिश्त के बांट नहीं पा रही हैं। आज काम करवाना एक ऐसा चमत्कार बनता जा रहा है जिसके पीछे भ्रष्टाचार की मौन स्वीकृतियाँ मौजूद हैं। सरकारें अगर चाहें, तो जनता और विकास से जुड़े कार्य इससे मुक्त हो सकते हैं। इसी सरकार ने जमीन इंतकाल के सैकड़ों लंबित मामले निपटा कर जनता को राहत और भ्रष्टाचार के बाहुपाश से मुक्ति दिलाई है। पूर्व में प्रेम कुमार धूमल ने जनता को कुछ सेवाओं की गारंटी देते हुए इनकी समयावधि तय की थी। जयराम सरकार ने आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए जनमंच आयोजित किए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के मार्फत जनता की शिकायतों का निवारण करने का तरीका भी ईजाद हुआ, लेकिन ये उपाय केवल इवेंट बन जाते हैं। कई तहें और कई राहें इतनी पुष्ट और मान्य हैं कि सरकारों के इरादे आगे चलकर सियासी जंजीर बन जाते हैं। इन्हीं में से निकलती हैं वेतन विसंगतियाँ, सेवा नियम, पदोन्नतियाँ और सेवाकाल का सेवानिवृत्ति के बाद विस्तार। हिमाचल में ट्रांसफर का अपना ही एक खजाना है, जहाँ भ्रष्टाचार के कई औजार और त्योहार छिपे हैं। यह दौर है कि सुक्यू सरकार कैडर में सुधार लाने की दृष्टि से इन्हें राज्य स्तरीय घोषित करने की राह पर चली है, लेकिन अभी भी राज्य सचिवालय की दमक और धमक के चलते कान बजते हैं। शिमला में सत्ता के इरादों को सचिवालय की दीमक चाट जाती है, इसलिए हिमाचल की सरकारी कार्यसंस्कृति में अनुपस्थित मानसिकता व जवाबदेही के अभाव से उत्पन्न होता है संशय। दुख यह कि उनकी करतूत हेरान नहीं करती, वरना सारे सबूत हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं। हिमाचल में ठेकेदारी प्रथा, आउट सोर्स सेवाएं और तरकीबों के नए अवसर कुछ तो अपने भीतर राज रखते हैं। नियमों की फेहरिस्त में जहाँ राजनीतिक आदेश जरूरी है, वहाँ थाने में रपट लिखाने से पहले भी सिफारिश ढूँढी जाती है। यही सिफारिश आगे चलकर भ्रष्टाचार का दूसरा पहलू बन जाती है। अगर डाक बंगलों की रौनक से खर्च की पर्चियाँ निकाली जाएं, तो दर्जनों जेई अपनी पाकेट को हमेशा कटी हुई पाएंगे। ऐसा क्यों है कि एचआरटीसी के साथ अनुबंधित निजी खटारा खाली बसें, अनुदान व तथ्यशुदा अधिमान पा रही हैं।

मराठी भाषा को मिला विशिष्ट दर्जा: मराठी भाषियों के लिए गर्व की बात

केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने रंगनाथ पठारे के नेतृत्व में एक समिति गठित की और केंद्र सरकार को 500 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने उनकी पहल पर मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का फैसला किया। इस निर्णय से महाराष्ट्र और दुनिया भर में मराठी भाषियों का गौरव बढ़ा है। अन्य भाषाएँ जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया शामिल हैं। मराठी का उच्चारण महारट्टी-महरट्टी-मूहाटी-ओर फिर मराठी हो गया। महाराष्ट्रीय भाषा महाराष्ट्र क्षेत्र के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से प्रचलित थी। मराठी की भाषाई यात्रा प्राचीन महारथी भाषा, मरहट्टी, महाराष्ट्रीयन, प्राकृत, भ्रष्ट मराठी और आज की मराठी से होकर गुजरी है। एल. घोष कहते हैं कि ये भाषाएँ अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही भाषा मराठी के रूप में हैं। निवासी। पंगारकर ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मराठी में उपलब्ध दो हजार वर्ष पुरानी पुस्तक गाथा सप्तशती या गाथा सतासई है। यह पुस्तक सत्रहवें सातवाहन राजा और कवि %हाल% द्वारा दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी। पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल स्टडीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग तीस हजार प्राचीन पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें से 80 ग्रंथ डेढ़ से दो हजार वर्ष पुराने हैं। इनमें मुख्य रूप से कालिदास की शकुंतला (चौथी शताब्दी), शूद्रक की मृच्छकटिक (छठी शताब्दी), प्रवरसेन की सेतुबंध (पांचवीं शताब्दी), भद्रबाहु की अयनम (तीसरी शताब्दी) आदि शामिल हैं। रामायण और महाभारत में भी सैकड़ों मराठी शब्द मिलते हैं। महाराष्ट्र का उल्लेख पाली और सिंहल भाषाओं में बौद्ध ग्रंथों विनय पिटक, दीपवंश और महावंश में किया गया

है। मराठी भाषा में पहला शिलालेख 2,220 वर्ष पूर्व का है, जो ईसा युग के आरंभ से भी पहले का है। यह ब्राह्मी लिपि में है। यह शिलालेख पुणे जिले के जुन्नार के निकट नानेघाट में पाया गया था। इसी प्रकार मराठी ग्रंथ 'लीलाचरित्र' और 'ज्ञानेश्वरी' को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्लासिक ग्रंथ का दर्जा दिया गया है।

मराठी भाषा के भौगोलिक क्षेत्र में पेंसड अलग-अलग बोलियाँ हैं। साहित्य में उन बोलियों के प्रयोग के कारण %मानक मराठी% दिन-प्रतिदिन समृद्ध होती जा रही है। मेरी बोली अहिरानी है, जो मराठी की एक घटक बोली है। ऐसा कहा जाता है कि यह भाषा दूसरी या तीसरी शताब्दी से बोली जाती रही है। कहा जाता है कि मानक भाषा मराठी भी उतनी ही पुरानी है।

110 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली मराठी, विश्व में 10वीं से 15वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भाषा है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए तथा विभिन्न शताब्दियों में विभिन्न लेखकों द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए, इसकी शास्त्रीयता को स्वयंसिद्ध बताया गया है।

शास्त्रीय भाषाएँ भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने का काम करती हैं। यह प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डालता है, यही वजह है कि मराठी भाषा को यह दर्जा मिला, यह सुनिश्चित करने के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं।

जिस राज्य को यह दर्जा दिया जाता है, उसे भाषा के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुदान मिलता है। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और एक लड़ाई जीती गई। यह हमारे मराठी भाषियों के लिए बहुत गर्व की बात है। शास्त्रीय भाषा भारत सरकार द्वारा किसी विशिष्ट भाषा को दिया गया दर्जा है।

शास्त्रीय भाषा के लिए मानदंड

प्राचीन साहित्य-संबंधित भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए तथा उसका प्राचीन साहित्य आज भी उपलब्ध होना चाहिए।

समृद्ध साहित्यिक परंपरा- भाषा में ऐसा साहित्य होना चाहिए जो प्राचीन काल से लेकर हाल के समय तक अस्तित्व में रहा हो और जिसने अपना महत्व सिद्ध किया हो। मूल भाषा- संबंधित भाषा अपनी स्वतंत्र भाषा होनी चाहिए, अर्थात् किसी अन्य भाषा से सीधे उधार नहीं ली गयी हो।

सांस्कृतिक महत्व- भाषा का उस समाज के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व होना चाहिए।

मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लाभ भाषा संरक्षण और सुरक्षा-सरकार मराठी भाषा के अनुसंधान और संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराएगी। इससे मराठी भाषा के संरक्षण और प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।

अनुसंधान को प्रोत्साहन- शास्त्रीय भाषाओं पर अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अनुदान और छत्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

शैक्षिक विकास-मराठी भाषा के प्राचीन साहित्य, संस्कृति और इतिहास को शैक्षिक पाठ्यक्रम में तेजी से शामिल किया जाएगा, जिससे मराठी छात्र अपनी भाषा का अधिक गहराई से अध्ययन कर सकेंगे।

मराठी भाषा में पारंपरिक रूप से मौलिकता, अखंडता और निरंतरता रही है। इसमें कोई लौकिक विभाजन नहीं है। मराठी भाषा में लीलाचरित्र और ज्ञानेश्वरी जैसे क्लासिक ग्रंथ भी हैं। अभिजात का अर्थ है श्रेष्ठ। यद्यपि मराठी भाषा का आधुनिक रूप उसके प्राचीन रूप से भिन्न है, फिर भी उनके बीच का आंतरिक संबंध स्पष्ट रूप से उजागर होता है।

प्राचीन मराठी भाषा और उसके आधुनिक रूप के बीच संबंध उसके व्याकरण के माध्यम से आसानी से स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ज्ञानेश्वर के समय की मराठी भाषा (13वीं शताब्दी) और आज की मराठी भाषा, शिव के समय की भाषा (17वीं शताब्दी) और 21वीं शताब्दी की भाषा एक ही है। यद्यपि 18वीं शताब्दी की मराठी भाषा और आज की मराठी भाषा में थोड़ा बहुत भाषाई अंतर है, फिर भी यह आसानी से स्पष्ट है कि भाषा एक ही है और भाषा विज्ञान के नियमों के अनुसार ये परिवर्तन केवल समय बीतने के कारण हुए हैं।

अब मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से मराठी बोलियों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा शोध एवं साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने से उसका दर्जा ऊंचा हुआ है और इसके संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए कई नए रास्ते खुले हैं।

मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने से अनेक अवसर खुलेंगे, विशेषकर सांस्कृतिक और अनुसंधान के क्षेत्र में। साथ ही, इन भाषाओं के प्राचीन साहित्य के संरक्षण, सूचना संग्रहण और डिजिटलीकरण के साथ-साथ विभिन्न साहित्य के अनुवाद, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया के माध्यम से रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे।

मराठी भाषा देश का गौरव है। यह सम्मान देश के इतिहास में मराठी भाषा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के योगदान को उजागर करता है। भारतीय परंपरा में मराठी का सदैव बहुत महत्व रहा है। मुझे यकीन है कि अब जब इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, तो कई लोग मराठी सीखने के लिए जरूर प्रेरित होंगे।

संकलन

श्वेता पोटेड

प्रभारी जिला सूचना अधिकारी गोंदिया

निधि वापस जाने की कगार पर दरगाह के लिए सरकार से 20 लाख रु. की निधि कराई गई थी मंजू

गोंदिया-अर्जुनी मोरगांव तहसील के प्रतापगढ़ में ख्वाजा उस्मान गनी की दरगाह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रतापगढ़ पहाड़ी श्रद्धा स्थल होने के कारण यहां बड़ी संख्या में दोनों धर्मों के लोग आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता की वजह से दरगाह के विकास के लिए आई सरकारी निधि वापस जाने की कगार पर है। श्रद्धालुओं ने भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। वर्ष भर में जिला समेत विदर्भ से भी मुस्लिम बंधु यहां दर्शन के लिए आते हैं। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता है। इसी कालावधि में ख्वाजा उस्मान गनी हारुनी की दरगाह पर उर्स का आयोजन किया जाता है। इन दिनों यहां हिंदू-मुस्लिम श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। दोनों धर्मों के श्रद्धालु एक-दूसरे के तीर्थ स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस वजह से यह स्थल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। इसी प्रकार यहां से



इटियाडोह बांध समीप होने से पर्यटन के लिए आने वाले नागरिक भी यहां भेंट देते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन संबंधित विभाग की उदासीनता की वजह से दरगाह की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से खराब हो गया है। शौचालय व पानी के लिए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथा सांसद प्रफुल पटेल ने प्रतापगढ़ दरगाह में भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख रु. की राशि मंजू कराई थी। इस निधि से विविध विकास कार्य अपेक्षित थे। लेकिन विभाग की उदासीनता की वजह से यह राशि वापस जाने की कगार पर है। इस वजह से यहां सड़क व शौचालय समेत अन्य काम रुके हुए हैं।

चोरी की बाइक में घूमते मिले आरोपी

लाखनी-लाखनी पुलिस ने पवनी पुलिस थाने के चोरी के मामले में वांछित आरोपी को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक हृदयनारायण यादव के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार अमितेश वडेठवार, महिला पुलिस हवलदार वासंती बोरकर, प्रभा कुलसुंगे और चालक पुलिस हवलदार संजय अरकासे लाखनी शहर में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बाजार क्षेत्र में एक सदिंध युवक मोटरसाइकिल पर घूमते हुए नजर आया। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोका और वाहन के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने टालमटोल भरे जवाब देने शुरू कर दिए। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया और वाहन के कागजातों की जांच की। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि लाल रंग की हीरो पैशन मोटोसाइकिल नंबर



एमएच 31 डीएन 4556 पवनी पुलिस थाने के अपराध क्रमांक 43/2025 के तहत चोरी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोंडा निवासी तेजराज उर्फ तेजेश जगदीश आडे (29) के रूप में हुई। वह पेशेवर वाहन चोर है और लाखनी, अड्याल, साकोली, पवनी और कारधा पुलिस थानों के तहत उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि तेजराज हाल ही में लाखनी पुलिस थाने के एक अन्य मामले में सजा पूरी कर जेल से बाहर आया था। पुलिस ने उसे चोरी की मोटरसाइकिल सहित पवनी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।

आदिवासी समाज ने धूमधाम से मनाया कोयापूनेम महोत्सव कचारगढ़ मेले में शामिल हुए लाखों श्रद्धालु

सालेकसा-पांच दिवसीय कोयापूनेम महोत्सव का आयोजन कचारगढ़ में हाल ही में किया गया था। इस महोत्सव में देशभर से आए गोंड आदिवासी समुदाय एवं अन्य समाज के नागरिकों ने भी गोंड समाज के आराध्य की पूजा-अर्चना की। पांच दिनों तक गोंडी धार्मिक परंपराओं, बोली, पूजा अनुष्ठानों, नृत्य, रीति-रिवाज, कला व संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव में 4 लाख से अधिक आदिवासियों ने गोंडी धर्म, कला व संस्कृति के दर्शन किए। महोत्सव में देशभर के करीब 18 राज्यों से गोंडी श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद करने यहां पहुंचे थे। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,



तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ओडिसा, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश के आदिवासी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी। साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात आदि 18 राज्यों के श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। गोंडी समुदाय ने कोयापूनेम उत्सव में हिस्सा लिया। महोत्सव में कई वरिष्ठ अधिकारी,

जिप विषय समिति सभापति के पदों का आवंटन 24 को

गोंदिया-जिला परिषद विषय समिति सभापति पद के लिए 10 फरवरी को चुनाव हुआ। इसके बाद सभापति को खाते आवंटन के लिए 24 फरवरी को जिप अध्यक्ष ने एक विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीन सभापतियों को वित्त और निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा कृषि व पशुपालन विभाग वितरित किए जाएंगे। गोंदिया जिला परिषद में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट सत्ता में हैं। ढाई साल पहले तय हुए गठबंधन फार्मूले के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 24 जनवरी को हुए थे। भाजपा के लायकराम भंडारकर अध्यक्ष चुने गए, जबकि राकांपा के सुरेश हर्षे निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। चर्चा थी कि विषय समिति के सभापति पद के चुनाव में भी यही फार्मूला जारी रहेगा। लेकिन 10 फरवरी को हुए विषय समिति सभापति पद के चुनाव में भाजपा ने चारों अध्यक्ष पदों पर भाजपा के ही सदस्यों को मैदान में उतारा। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सभापति पद से दूर रखा। विधायक विनोद अग्रवाल की भाजपा में वापसी के साथ ही उनका प्रमुख संगठन भी भाजपा में विलीन हो गया। जिससे जिला परिषद

में भाजपा की ताकत बढ़ गई। क्योंकि भाजपा के पास 32 सदस्यों का बहुमत है, इसलिए अब उन्हें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने भाजपा के सभी चार सदस्यों को सभापति नियुक्त कर दिया। अब चर्चा है कि एनसीपी को विभागों के आवंटन में कृषि व पशुपालन विभाग दिया जाएगा। निर्माण सभापति पद पर भगत जिला परिषद की कुल पांच विषय समिति सभापति में से पूर्णमा देंगे को महिला व बाल कल्याण सभापति तथा रजनी कुंभरे को सामाजिक कल्याण सभापति के रूप में चुना गया। अब वित्त व निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा कृषि पशुपालन विभाग के सभापति पदों का आवंटन 24 फरवरी को किया जाएगा। इसमें वित्त व निर्माण विभाग के सभापति पद पर डा. लक्ष्मण भगत, शिक्षण व स्वास्थ्य सभापति पद पर दीपा चंद्रिकापुरे नियुक्त किए जाने की संभावना है। जिप उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे के पास कृषि व पशुपालन विभाग रहने की संभावना है। विभिन्न समितियों में शामिल होंगे सदस्य जिला परिषद में जल व्यवस्थापन समिति सहित विभिन्न समितियों में सदस्यों की भर्ती की जाएगी। यह नियुक्ति भी जिप अध्यक्ष लायकराम भंडारकर की अध्यक्षता में की जाएगी।

शिक्षक का कारनामा, स्कूल में मचा हड़कंप छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज

गोंदिया-शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षकाने उसी स्कूल के शिक्षक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। शिक्षक की पत्नी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी शिक्षक का नाम प्रकाश परशुरामकर बताया गया है। शिक्षा क्षेत्र में एक ओर जहां अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की शिक्षा दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देवरी में एक घटना घटी जहां एक शिक्षक ने अपने स्कूल के शिक्षक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इस निंदनीय घटना से शिक्षा क्षेत्र और अभिभावकों में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक प्रकाश परशुरामकर पिछले कुछ वर्षों से देवरी के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। यह शिक्षक स्कूल के दूसरे शिक्षक के घर जाता है और उसकी पत्नी को दो हजार रु. देता है और उसने शर्मनाक हरकत करके उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित महिला ने इस संबंध में शिक्षक के खिलाफ देवरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। देवरी पुलिस ने आरोपी शिक्षक प्रकाश परशुरामकर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गीता मुले कर रही है। इस निंदनीय घटना से शिक्षा क्षेत्र और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। मामला दर्ज करने की नहीं मिली जानकारी हमने स्कूल में कार्यरत शिक्षक प्रकाश परशुरामकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हमें अभी तक पुलिस थाने से यह जानकारी नहीं मिली है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही हम संस्था संचालक को शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजेंगे।

-जी.एम. मेश्राम, प्राचार्य, देवरी

राष्ट्रवादी काँग्रेस द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया सांसद प्रफुल पटेल व वर्षा पटेल का जन्मदिन

बुलंद-गोंदिया-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी गोंदिया द्वारा सांसद प्रफुल पटेल व वर्षा पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी भवन रेलटोली कार्यालय में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन व पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ केक काटकर मिठाईयां बांटी गईं व आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही उनकी स्वास्थ्य जीवन व दीर्घायु की शुभकामनाएं की। इस अवसर पर राष्ट्रवादी काँग्रेस व प्रयास बहुउद्देशीय सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन कर अनेकों ने रक्तदान किया। रक्तदान में बाई गंगाबाई रुग्णालय के डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारीओ का



सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सर्वश्री राजेन्द्र जैन, प्रेमकुमार राहंगडाले, सुरेश हर्षे, देवेन्द्रनाथ चौबे, प्रभाकर दोनोडे, राजलक्ष्मी तुरकर, बालकृष्ण पटले, टी एम् पटले, नानू मुदलियार, राजू एन जैन, केतन तुरकर, जगदीश बावनथडे, शिवलाल जमरे, नीरज उपवंशी, माधुरी नासरे, आशा पाटिल, कुंदा दोनोडे, शर्मिला पाल, रवि पटले, अखिलेश सेठ,

किरण पारधी, अनूज जायसवाल, विजय राहंगडाले, प्रदीप रोकडे, लखन बहेलिया, संजीव राय, रमण उके, सौरभ जायसवाल, करण टेकाम, नितिन टेंभरे, हरिराम आसवानी, सुनील पटले, शैलेश वासनिक, नागो बन्सोड, कपिल बावनथडे, अविनाश महावत, रौनक ठाकुर, दिलीप डोंगरे, पंकज चौधरी, गोविन्द लोचंडे, मंगेश रंगारी, किशोर पारधी, सुनील ब्राम्हणकर, घनश्याम फाये, विनोद पटले, प्रशांत सोनपुरे, प्रमोद लांजेवार, कुणाल बावनथडे, आकाश वाढवे, विनोद बोहरे, राजकुमार तवाडे, सचिन बंसोड, चौकलाल येडे, लंकेश पटले, सुरेंद्र कटरे, पप्पू ठाकरे, सुभाष यावलकर, बबलू बिसेन, प्रमोद मेंडे, महेंद्र राहंगडाले, विजय भांडारकर, श्रेयस खोब्रागडे, राहुल गेडाम, रमाकांत मेश्राम, राजू बावनथडे, अजय चव्हाण, संदीप बानेवार सह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राकांपा ने मनाई शिवाजी की जयंती



गोंदिया-जाणता राजा, आराध्य दैवत, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी द्वारा उत्साह के साथ मनाई गई। स्थानीय सूर्यटोला स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा माल्यार्पण व अभिवादन किया गया। इस अवसर पर आर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता पर शौर्य गाथा प्रस्तुत की। जयंती अवसर पर यावेळी राजेंद्र जैन के साथ ही देवेन्द्रनाथ चौबे, नानू मुदलियार, केतन तुरकर, विनीत सहारे, सुनील पटले, शैलेश वासनिक, अनूज जैसवाल, राजेश दवे, नागो बंसोड, करण टेकाम, पंकज चौधरी, लिकेश चिखलेंडे, प्रशांत सोनपुरे, लव माटे, सोहनलाल गौतम, हर्षवर्धन मेश्राम, श्रेयस खोब्रागडे, सरिता ब्रह्मे, उमा सिंग, पुष्पा मेश्राम, विजया उके, योगिता डोंगरे, संदीप बोरकर, धनलाल राहंगडाले, बहादुर कटरे, किसन वाढवे, दामोदर राहंगडाले, अरुण तुपकर, आकाश वाढवे, भूषण पाटिल, टीनु खंडारे, भजन सुखदेवे, यश खोब्रागडे, सार्थक बोरकर, अमन घोडीचोर, तुषार उके, कपिल बावनथडे, कुणाल बावनथडे, हर्षवर्धन मेश्राम, रमाकांत मेश्राम, रौनक ठाकुर, दिलीप डोंगरे, प्रकाश बरैया, मंगेश रंगारी, शरभमिश्रा, वामन गेडाम सहित कार्यकर्ता, नागरिक व विद्यार्थी उपस्थित थे।

वन्य प्राणी बाध, तेंदू के अंगों की तस्करी मामले में वन विभाग ने किया तीन आरोपियों को गिरफ्तार

सड़क अर्जुनी-जिले में वन्य प्राणियों की शिकार की घटनाएं एवं दुर्घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं, वहीं अंगों की तस्करी भी की जा रही है। इसी बीच 19 फरवरी को सड़क अर्जुनी वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणियों के अंगों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को वनविभाग ने गिर तार किया है। आरोपियों का नाम दल्लि (हलबीटोला) निवासी विठ्ठल मंगरू सराटी, भंडारा जिले के साकोली के मुंडीपार निवासी हरिष लक्ष्मण लांडगे व पिंपरी/गोंडमरी निवासी घनश्याम श्यामराव ब्राम्हणकर बताया गया है। जानकारी के अनुसार नागपुर (सतकंता) विभागीय वनाधिकारी पी.जी. कोडापे को मिली गुप्त जानकारी के आधार सड़क अर्जुनी वनपरिक्षेत्र में बाध, तेंदू आ वन्यप्राणियों के अंगों की बिक्री करने वाले आरोपियों पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, वहीं फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपी से बातचीत कर आरोपी को ग्रामीण अस्पताल सड़क अर्जुनी के पास के क्षेत्र से हिरासत में लेकर वन परिक्षेत्राधिकारी सड़क अर्जुनी स्थित कोहमारा में लाया गया। आरोपी विठ्ठल मंगरू सराटी को तलाशी लेने पर उसके पास से लकड़ी की पट्टी पर बाध/तेंदू की 22 मुंछें, दो दांत और एक उदबिलाऊ पाया गया। वहीं उसके पास से एक देशी पिस्तौल भी जब्त की गई। आरोपी हरिष लांडगे व घनश्याम ब्राम्हणकर के पास कुछ भी नहीं मिला। आरोपी बाघों/तेंदुओं का शिकार करने और उनके अंगों को बेचने के आरोपों में लगे हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर



न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 21 फरवरी तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है। जांच उप वनसंरक्षक प्रमोदकुमार पंचाभाई के मार्गदर्शन में डोंगरगांव के सहायक वनसंरक्षक एस.एम. डोंगरवार कर रहे हैं। यह कार्रवाई नागपुर (सतकंता) विभागीय वनाधिकारी पी.जी. कोडापे, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के उपसंचालक पवन जेफ सहायक वनसंरक्षक एस.एम. डोंगरवार, सड़क अर्जुनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोंगे, गोंदिया के वनपरिक्षेत्र अधिकारी रविकांत भगत, डोंगरगांव के वनपरिक्षेत्र अधिकारी सी.बी. भडंगे, विशेष व्याघ्र संरक्षण दल क्र. 1 के वनपरिक्षेत्र अधिकारी पी.एम. पझारे, कोहमारा के क्षेत्र सहायक एस.के. पटले, रेंगेपार के क्षेत्र सहायक सी.एस. डोरले, जांभली के क्षेत्र सहायक यु.पी. गोटाफेडे, डुंगीपार के पी.बी. चव्हाण, सौंदर के पी.एम. पटले, कोहमारा के एम.वी. चव्हाण, कनेरी के एच.एम. बागलकर, खोबा के आई.पी. राऊत, मोगरां के डी.डी लांजेवार, पी.बी. कांबले व विशेष व्याघ्र संरक्षण दल क्र.1 नवेगांवबांध के समीर बंसोड, वाहन चालक व आदि कर्मचारियों ने की।

लाठी से मारपीट कर झूठे मामले में फंसाने की दी धमकी

गोंदिया-ग्रामीण थाने के तहत सिविल लाइन, गोंदिया निवासी फियादी विवेक कैलास तावाडे (25) के पिता ने पोवारीटोला (अदासी) निवासी आरोपी खेहल सुनील राऊत (21) को ब्याज पर पैसे दिए थे। फियादी वह पैसे लेने आरोपी के घर गया। इस



दौरान आरोपी ने उसे कुर्सी फेंक कर मार दिया। वहीं लाठी से मारपीट कर गालीगलौज की तथा झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी। फियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच हवलदार कामडे कर रहे हैं।

महिलाओं ने गुट विकास अधिकारी के कक्ष में फोड़ी गागर



गोंदिया-सड़क अर्जुनी तहसील अंतर्गत आनेवाले डव्वा के वार्ड क्रमांक 2 में ग्रीष्मकाल शुरू होने के पहले ही पेयजल की समस्या निर्माण हो गई है। जिसे लेकर महिलाओं ने गागर मोर्चा निकाला। ग्राम पंचायत ने वार्ड क्रमांक 2 में स्थित हैंडपंप को ठक्कर बापा योजना से सौर ऊर्जा नल जलापूर्ति पानी टंकी लगाने का निर्णय लिया। लेकिन शिकायतकर्ता के मकान के सामने उक्त हैंडपंप है। जिसका विरोध किए जाने से कार्य नहीं हो पाया। विशेष बात यह है कि शिकायतकर्ता की हैंडपंप के सामने सुरक्षा दीवार युक्त प्लॉट है। एक ही रात में हैंडपंप के सामने द्वार बनाया गया। मकान के सामने हैंडपंप लगाने पर ग्राम पंचायत द्वारा सौर पंप नहीं लगाया जा सका। जिससे वार्ड क्रमांक 2 के माल्ही मोहल्ले में पेयजल की समस्या निर्माण हो गई है। इस समस्या को लेकर वार्डवासियों ने 18 फरवरी मंगलवार को सड़क अर्जुनी पंचायत समिति पर गागर मोर्चा निकाला। जिसका नेतृत्व सरपंच योगेश्वरी चौधरी ने किया। इस बीच मोर्चे में शामिल महिला व

पुरुष काफी आक्रोशित नजर आए। जिससे गुट विकास अधिकारी को पुलिस दल को बुलाना पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने गुट विकास अधिकारी के समक्ष पेयजल की समस्या रखी और उनका घेराव किया। इतना ही नहीं तो गागर को गुट विकास अधिकारी के कक्ष में फोड़कर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस समय गुट विकास अधिकारी रविकांत सानप, सभापति चेतन वडगाये, उपसभापति निशा काशिवार को ज्ञापन देकर आगामी 10 दिनों में पेयजल की समस्या हल करने की मांग की गई। जिस पर गुट विकास अधिकारी ने 15 दिनों के भीतर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सभापति चेतन वडगाये, उपसभापति निशा काशिवार, पंस सदस्य शालिंदर कापगते, सरपंच योगेश्वरी चौधरी, खोड़शिवनी के सरपंच गंगाधर परशुरामकर उपस्थित थे।

यातायात विभाग की कार्रवाई शुरू

वसूला जुर्माना कानफोड़ साइलेंसर वाली 21 बाइक जब्त

गोंदिया-यातायात विभाग ने बुधवार रात को उन मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ अभियान चलाया, जो कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए साइलेंसर से छेड़छाड़ कर तेज आवाज और पटाखे जैसी आवाज निकालते थे। लगभग एक घंटे तक चले अभियान में 21 से अधिक बाइकें जब्त की गईं। यातायात विभाग ने उन्हें आदेश दिया कि पहले संशोधित साइलेंसर हटाएं, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया साइलेंसर लगाएं और उसके बाद ही बाइक ले जाएं, इतना ही नहीं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। साइलेंसर में छेड़छाड़ करने पर यह पटाखे जैसी आवाज निकालता है। बच्चों और बुजुर्गों सहित आम जनता रात में शहर में पटाखों जैसी आवाजें निकालते हुए घूमने वाले मोटरसाइकिल चालकों से तंग आ आ चुके चुक हैं। इस संबंध में पुलिस को भी शिकायतें प्राप्त हुईं। जब यह बात सामने आई कि पिछले आठ-दस दिनों में ऐसे मोटरसाइकिलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, तो यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक नागेश भास्कर और उनके सहयोगियों ने एक-दो नहीं, बल्कि पिछले एक साल में सैकड़ों बुलेट जब्त कीं। इन सभी वाहनों को पुलिस थाने ले जाया गया और उनके मालिकों को बुलाया गया। बाइक मालिकों को संशोधित साइलेंसर को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए साइलेंसर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।



परिवहन शाखा यहीं नहीं रुकी। प्रत्येक पर 1,000 रु. का जुर्माना भी लगाया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की कड़ी नजर प्रशासन ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शोर करने वाले साइलेंसर लगाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुलेट चालक साइलेंसर को इस तरह संशोधित कर लेते हैं कि इससे कान फटने जैसी आवाज निकले और दूसरों का ध्यान आकर्षित हो। लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों पर पुलिस कड़ी नजर रखती है। अनावश्यक तेज आवाज निकालने पर होगी कार्रवाई कंपनी के साइलेंसर को मोटरसाइकिल मालिकों द्वारा संशोधित किया जा रहा है। आम जनता को तेज आवाज और आतिशबाजी के शोर से परेशानी हो रही है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए परिवहन विभाग द्वारा मोटरसाइकिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नागेश भास्कर, पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा, गोंदिया

नप कार्यालय के तंबाकू शौकीनों पर एवशन 11 लोगों पर लगा 1320 रुपये जुर्माना

गोंदिया-राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के.टी.एस. जिला सामान्य अस्पताल के तहत नगर परिषद कार्यालय में कार्रवाई अभियान चलाया गया। इसमें कार्यालय परिसर में तंबाकू सेवन करते पकड़े गए 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 1320 रु. का जुर्माना लगाया गया। सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों को तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर प्रतिबंध है। जिसके अनुसार, जिलाधीश प्रजोत नायर के आदेश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकारी कार्यालयों में अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रकार जिला शल्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में नगर परिषद कार्यालय में अभियान

चलाया गया। टीम ने कार्यालय के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण किया। इसके अलावा, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत तंबाकू और गुटखा का सेवन और उसे रखने वाले 11 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई और 1,320 रु. का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी सी. ए. राणे, जिला सलाहकार डा. ज्योति राठोड, जिला मनोवैज्ञानिक सुरेखाआजाद मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ता संस्था शंभरकर, दंत सहायक विवेकानंद कोरे, टैक्स प्रशासनिक अधिकारी भूमेश्वरी झलके, पी.सी. पवार, सीमा बरेकर, पुलिस कर्मचारी एस. सी. पटले द्वारा की गई।

कीटाणुशोधन के बाद ही दें पेयजल संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सीईओ मुरुगानथम के निर्देश

गोंदिया-जिले में जीबीएस वायरस और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल का कीटाणुशोधन, परीक्षण, क्षेत्र की सफाई, जल आपूर्ति योजनाओं में रिसाव, पेयजल का कीटाणुशोधन, स्रोतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जनजागृति करना आवश्यक है। इसके लिए सभी पेयजल स्रोतों, वितरण प्रणालियों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और घरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी के नमूनों को गांव में प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकों द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके महीने में एक बार जैविक और रासायनिक रूप से परीक्षण किया जाए, ऐसे निर्देश जिला परिषद के सीईओ मुरुगानथम ने दिए। जिले में स्वच्छ जल आपूर्ति के प्रावधान के अनुरूप ग्राम स्तर पर नल जल आपूर्ति योजनाओं के सभी स्रोतों से स्कूलों, आंगनवाड़ियों व घरों में नलों के माध्यम से उपलब्ध जल के जैविक परीक्षण के लिए आवश्यक जल नमूने एकत्रित कर नजदीकी भूजल सर्वेक्षण व विकास प्राधिकरण को प्रयोगशाला में जमा कराएँ, जीबीएस और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला जैविक परीक्षण आवश्यक है, उन्होंने ऐसे निर्देश जीबीएस और अन्य संक्रामक रोगों से निपटने के लिए जिला परिषद जल आपूर्ति व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित बैठक में



दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए तथा पेयजल आपूर्ति के संबंध में सतर्कता बरती जाए, जीबीएस और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए जिला परिषद ने पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम पंचायत विभागों के समन्वय में विभिन्न पहल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। यदि गांव में जीबीएस के संदिग्ध मरीज पाए जाते हैं तो इसकी सूचना तुरंत जिला स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दी जाए और तत्काल उपाय किए जाए, उस गांव के सभी जल स्रोतों को शुद्ध किया जाए और सभी पेयजल के नमूने तुरंत एकत्र करके प्रयोगशाला में भेजे जाए, प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध करें ग्रामीण क्षेत्रों में,



प्रत्येक परिवार को कार्यात्मक घरेलू पाइप कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 55 लीटर निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए, इसका मुख्य

समाज में होती है महिलाओं की सुरक्षा अहम न्यायमूर्ति गायकवाड ने कानून पर दी जानकारी

साकोली-विधि सेवा समिति साकोली तथा महिला आर्थिक विकास भंडारा द्वारा सबला लोकसंचालित सधन केंद्र साकोली सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता दिवानी न्यायाधीश वी. एम. गायकवाड ने की और मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता अशोक करवडे उपस्थित थे। न्यायमूर्ति गायकवाड ने सबसे पहले विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और उन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही उन्होंने नारी सशक्तिकरण, महिला संबंधित कानूनों और उनके विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी



मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को होनेवाले अत्याचारों के बारे में समय रहते उसकी जानकारी लेनी चाहिए और विधि सेवा समिति में शिकायत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कमजोर वर्ग के लिए विधि सहायता के बारे में भी जानकारी दी और संविधान सा द्वारा दिए गए अधिकारों को जीवन में कैसे मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना कल्याणी गांधीभये, संचालन ममता बांबुर्डे ने किया और आयोजन

की जिम्मेदारी सुनील कापगते ने ली। कार्यक्रम में न्यायालयीन कर्मचारी राजू नेवारे, पीएलवी एल. ए. मल्लानी, मनोहर लोथे, बबीता वासनिक, संदीप बारसागडे, सहयोगी शशिकला कोवाची, कुमुद नंदेश्वर, प्रमिला हुमणे, रेखा भोंडे, अर्चना शहारे सहित अन्य सभी सहयोगी दिए गए अधिकारों को जीवन में कैसे मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना कल्याणी गांधीभये, संचालन ममता बांबुर्डे ने किया और आयोजन

परिवारिक हिंसा से बचने का सुझाव दिया अशोक करवडे ने पोक्सो कानून के तहत महिलाओं को अपने बच्चों के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में विस्तार से बताया, उन्होंने पोक्सो कानून में महिलाओं के लिए प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि इस कानून के तहत दोषी को विशेष न्यायालय में सुनवाई करके 20 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही, उन्होंने हिंदू सक्सेरून एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में भी बताया और परिवारिक हिंसा से कैसे बचा जा सकता है, इस पर मार्गदर्शन किया।

अग्निशिखा ई-बुक और ऑडियो बुक के माध्यम से अगली पीढ़ी तक सुषमा स्वराज की जीवन यात्रा-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

बुलंद गोंदिया (मुंबई)- सुषमा स्वराज एक अध्ययनशील, विद्वान और चतुर व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और विदेश मंत्री के रूप में शानदार काम किया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मेघदूत निवास पर अग्निशिखा ऑडियो और ई-बुक के विमोचन के दौरान विश्वास व्यक्त किया कि ई-बुक और ऑडियो बुक अग्निशिखा सुषमा स्वराज के माध्यम से उनका कार्य और जीवन यात्रा निश्चित रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी।



मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थीं तो उन्होंने पासपोर्ट और वीजा के संबंध में कई कदम उठाए थे। आज हमें कई देशों से वीजा मिल रहा है, क्योंकि उनके साथ हमने समझौते किए हैं। उनके द्वारा किए गए सुधारों की बदौलत आज पासपोर्ट प्राप्त करना आसान हो गया है। जब वे लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, उस समय तत्कालीन सरकार के प्रशासन पर उनकी व्यावहारिक टिप्पणियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं। उनका परिश्रम, विषय को संभालने की क्षमता, स्मरण शक्ति तथा उनकी अपार बुद्धि उन्हें

पहचानने के लिए पर्याप्त है।

उनमें विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने तथा उनके भीतर भाषा के सौंदर्य को पहचानने की विशेष प्रतिभा थी। सुषमा स्वराज बोलते समय कभी भी अपने सामने कागज नहीं रखती थीं। यह उनकी विशेषता थी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सुषमा स्वराज के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके व्यावहारिक भाषण आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं।

मेधा किराट द्वारा लिखित पुस्तक की ऑडियो बुक और ई-बुक तीन भाषाओं - मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। पुस्तक का डिजिटल निर्माण इंकार स्टूडियो, पुणे में किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद किराट सोमैया, मराठी कथावाचक तनुजा रहाणे, ई-बुक लेखिका स्वाति जोशी, हिंदी कथावाचक दिव्या शारदा, इंकार के निर्देशक सत्यजीत पंगु और आनंद लिमये उपस्थित थे।

मिलिंद सालवे भंडारा जिप के नए सीईओ

मुंबई-राज्य सरकार ने मंगलवार को नौ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। नौ आईएएस मिलिंद अधिकारियों सालवे को जिला के तबादले परिषद भंडारा के कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर भेजा गया है। गडचिरोली के परियोजना निदेशक व सहायक जिलाधिकारी राहुल कुमार को लार्ज जिला परिषद का सीईओ बनाया गया है। डॉ. विजय सूर्यवंशी को कोंकण विभाग का आयुक्त बनाया गया है। अब तक वे आबकारी विभाग के आयुक्त थे, जबकि कोंकण के विभागीय आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख को सूर्यवंशी के स्थान पर आबकारी आयुक्त के पद पर भेजा गया है।

इसके अलावा आदिवासी विभाग आयुक्त नयना गुंडे को पुणे में महिला व बाल कल्याण विभाग का आयुक्त बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की परियोजना निदेशक विमला आर. अब नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में स्थानीय आयुक्त होंगी। अहिल्याबाई नगर के जिलाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ को चीनी आयुक्त (पुणे) के पद पर भेजा गया है। धाराशिव के जिलाधिकारी अब सोलापुर मनपा के आयुक्त होंगे, जबकि राज्य को-ऑपरेटिव आदिवासी विकास निगम की प्रबंध निदेशक लीना बनसोड को नाशिक में आदिवासी विकास विभाग आयुक्त के पद पर भेजा गया है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक 1356 बीमारियों के लिए सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई - अशोक उडके, आदिवासी विकास मंत्री

पारी कोपर लिंगो मा काली कंकाली मंदिर कचारगड कोया पुणेन यात्रा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

बुलंद गोंदिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर सालेकसा तहसील में स्थित कचारगड आदिवासी समुदाय की जन्मभूमि है और पूरा आदिवासी समुदाय यहां श्रद्धा के साथ आता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हर साल माची पूर्णिमा के अवसर पर करीब पांच से छह लाख श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए अपनी मन्त्रों मांगने यहां आते हैं। सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से उन लाखों श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।



यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी और जिला स्वास्थ्य प्रशासन के संयुक्त सहयोग से कचारगड में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

इस भव्य स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उडके और महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय विकास मंत्री अशोक उडके ने किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री फगनसिंह कुलस्ते, सांसद डॉ. नामदेव किरसान, भोजराज नाग, महेंद्र कश्यप, विधायक संजय पुराम, डॉ. परिणय फुके, रामदास मसराम, नामदेव उर्सेडी, पूर्व सांसद अशोक नेते, पूर्व विधायक भैरसिंह नागपुरे और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उडके ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की संकल्पना के अनुरूप आदिवासी भाई-बहनों के परिवारों को स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने के लिए महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1356 बीमारियों का मुफ्त इलाज मिलेगा। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को मिलाकर इस योजना के तहत नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए अपना गोल्डन कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं।

भविष्य में गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति से बचने के लिए आप आज ही आयुष्मान कार्ड बनवाएं और योजना का लाभ उठाएं। यह कार्ड सीएससी केंद्रों, आपले सरकार केंद्रों, ग्राम पंचायतों के सेतु केंद्रों, इस योजना के तहत स्वीकृत अस्पतालों और वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उडके ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के दौरान जिले के विशेषज्ञ चिकित्सक, ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक एवं उनकी पूरी टीम मौजूद थी। इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, मोतियाबिंद, किडनी एवं पेट रोग, मस्तिष्क रोग एवं अन्य गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच, दवा एवं प्रयोगशाला परीक्षण किए गए, जिसका अधिकांश श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। इस समय स्वास्थ्य विभाग, के.टी.एस. सामान्य चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बाई गंगाबाई महिला चिकित्सालय द्वारा आयोजित 50 जागरूकता स्टॉलों के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जनजागरूकता पैदा की गई।

कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे, जिला परिषद समाज कल्याण सभापति रजनी नागपुरे, पंचायत समिति अध्यक्ष गोंदिया मुनेश्वर

राहंगडाले, जिला कलेक्टर प्रजीत नायर, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, परियोजना अधिकारी गोंदिया उमेश काशिश, परियोजना अधिकारी चंद्रपुर विकास राचेलवार, उपविभागीय अधिकारी देवरी कविता गायकवाड़, तहसीलदार सालेकसा नरसय्या कोंडगुरले, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. अमरीश मोहवे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितिन वानखेडे, नगर पंचायत मुख्य अधिकारी देवरी संजय उडके, सालेकसा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल आत्राम, निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारती जायसवाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरेकसा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. पारस गिरी सहित विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिला समन्वयक, आशा कार्यकर्ता एवं आदिवासी बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत कचारगड सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गादास कोकोडे ने की। कार्यक्रम का संचालन भरत मडवावी ने किया, जबकि विधायक संजय पुरम ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

शासकीय धान खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई

बुलंद गोंदिया। सरकार ने पहले सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीद योजना के तहत खरीद विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान खरीदने की समय सीमा 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी थी। हालांकि, इस अवधि के दौरान पंजीकृत किसानों द्वारा धान की पर्याप्त खरीद नहीं होने के कारण सरकार ने समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि, गोंदिया के जिला कलेक्टर ने जिले के धान किसानों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपने धान को नजदीकी सरकारी धान खरीदी केंद्र पर बेचकर सरकार की धान खरीदी योजना का लाभ उठाएं।



जिले में खाद्य उद्यमियों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से लिए प्रशिक्षण

बुलंद गोंदिया-फॉस्टेक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की एक पहल है और इसका संचालन भारत सरकार और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से किया जाता है। FOSTECH प्रशिक्षण फरवरी 2025 में गोंदिया में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण की तैयारी के लिए शहर के होटल व्यवसायियों की एक बैठक होटल पैसिफिक रेलटोली में आयोजित की गई। यह प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रशिक्षण साझेदार के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और यह पूर्णतः निःशुल्क होगा। सहायक आयुक्त संजय शिंदे ने व्यवसाय की ओर से भाग लेने वाले मालिकों, रसोइयों और पर्यवेक्षकों से इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने की अपील की है, साथ ही प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए होटल, रेस्तरां और खानपान व्यवसाय के लाइसेंस की एक प्रति भी साथ लानी होगी। इस बैठक में गोंदिया सिटी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश शेट, उपाध्यक्ष राजेश चावड़ा, सचिव रमेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष



ललित सिंह भाटिया एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। होटल, रेस्तरां और खानपान व्यवसाय संचालकों के लिए प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी है, इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि व्यवसाय की विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी बढ़ती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना और खाद्य व्यवसाय

संचालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है, साथ ही ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान करना है।

फॉस्टेक प्रशिक्षण से खाद्य सुरक्षा मानकों का उचित अनुपालन करना आसान हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। ग्राहकों को यह आश्वासन भी मिलता है कि होटल या रेस्तरां में सभी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का पालन किया जा रहा है। कर्मचारी स्वच्छता, खाद्य प्रबंधन और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में अधिक जागरूक और प्रशिक्षित हो जाते हैं। यदि कोई व्यवसाय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द होने का खतरा रहता है। फॉस्टेक प्रशिक्षण इन जोखिमों को कम करता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, भाग लेने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों को FOSTECH प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। अतः आग्रह है कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोग इस प्रशिक्षण का लाभ उठाएं।

दीवार तोड़कर ग्राप कार्यालय में मुसा टूक

देवरी-महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सटे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर शिरपुरबांध ग्राम पंचायत की सुरक्षा दीवार को तोड़कर एक टुक अंदर घुस गया। यह घटना 16 फरवरी को शाम 4 बजे के आसपास घटित हुई गनीमत यह रही है कि इस घटना में कोई हानि नहीं हुई। टुक क्रमांक सी.जी.07/ए.ई. 6786 नागपुर से रायपुर की ओर रेलवे की सामग्री भरकर जा रहा था। लेकिन अचानक वाहन चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और यूरटन लेते समय सड़क के किनारे स्थित शिरपुरबांध ग्राम पंचायत कार्यालय की सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए टुक कार्यालय में घुस गया। हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं हुई। लेकिन ग्राम पंचायत को जरूर नुकसान पहुंचा है।

50 हजार रु. नकद चोरी

गोंदिया -आमगांव थाने के तहत कट्टीपार निवासी फियादी ताराचंद शिवा जंभुलकर (71) ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 50 हजार रु. निकास और वह साइकिल से साप्ताहिक बाजार करने चले गया। उसने 50 हजार रु. अपनी साइकिल पर थैले में डालकर रखा था। जिसे अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

2 अपराधियों से 80 हजार रु. नकद ज्वल आमगांव पुलिस टीम ने की कार्रवाई

गोंदिया-आमगांव पुलिस थाने की अपराध जांच टीम ने गहन जांच कर दो अलग-अलग चोरी के मामलों में चोरी की गई 80 हजार रु. नकद ज्वल कर दो शांति अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 14 फरवरी को आमगांव के साप्ताहिक बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति के बैग से 50 हजार रु. अज्ञात व्यक्तियों चोरी कर लिए थे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी थी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया. आमगांव थाने के अपराध निरोधक टीम को 18 फरवरी को गश्त के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल से संदिग्ध घुमते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने उनका पीछा कर आमगांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास उन्हें पकड़ लिया. संदिग्धों में से एक को बैंक में लोगों पर नजर रखते देखा गया. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्रीनगर, गोंदिया निवासी योगेश राजकुमार मुरादवानी (40) बताया. जब उससे पूछा गया कि वह बैंक में क्यों आया है तो उसने टालमटोल जवाब दिया.



मोटरसाइकिल के पास खड़े व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम गौतम नगर, गोंदिया निवासी विलास घनशाम मानकर (23) बताया. उन्हें हिरासत में लेकर गहन पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबुल किया. उनके पास से 80 हजार रु. नकद ज्वल किए गए. जांच हवलदार असिम मन्यार कर रहे हैं. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक तितपति राणे, सहायक पुलिस निरीक्षक निलेश डाबेराव, हवलदार असिम मन्यार, हवलदार दुधराम मेश्राम, दसरे, खुशालचंद बर्वे, सिपाही विनोद उपराडे, चेतन शेंडे, विक्रान्त सलामे, भागवत कोडापे, नितिन चोपकर, अक्षय कावरे ने की.

अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इलाज करने पहुंचेगी मोबाइल वैन

» उपचार और जांच निःशुल्क की जाएगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम वैन में रहेगी

गोंदिया-गोंदिया जिला आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित जिले के रूप में जाना जाता है। 18 फरवरी को दादालोरा खिड़की योजना अंतर्गत जिले में एक मोबाइल हॉस्पिटल (वैन) का लोकार्पण किया गया। इस मोबाइल वैन में शालिनीताई मेधे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर बानाडोंगरी, नागपुर के स्त्रीरोग, अस्थीरोग, नेत्ररोग, बालरोग, दंतरोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, किडनी रोग विशेषज्ञ, हृदयरोग विशेषज्ञ की टीम उपस्थित रहेगी और यह गोंदिया जिले के आदिवासी बहुल विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में घूमकर नागरिकों की निःशुल्क जांच एवं उपचार करेगी। पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे की संकल्पना एवं अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन में उपक्रम के अंतर्गत जिले के दुर्गम, अतिदुर्गम क्षेत्र के गरीब आदिवासी बंधुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा घर पहुंच मिल सके इसके लिए जिला पुलिस दल, ट्रायबल केल फेयर कमेटी, रोटी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3030 सह आयोजक शालिनीताई मेधे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर वानाडोंगरी, नागपुर जीवन आधार सामाजिक संस्था एवं माहुली मित्र मंडल नागपुर के संयुक्त प्रयासों से



मिले इस मोबाइल अस्पताल का लोकार्पण किया गया। उपरोक्त संस्थाओं के सहयोग से गोंदिया जिला पुलिस ने अनेक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये हैं। वर्ष 2022 से 2024 के दौरान सभी शस्त्र दूर क्षेत्र चिकित्सकों के अंतर्गत ऑपरेशन रोशनी चलाया गया, जिसके तहत मोतियाबिंदु जांच एवं ऑपरेशन किये गये। अब तक 3800 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ लिया और 300 से अधिक मोतियाबिंदु ऑपरेशन निःशुल्क किए। लोकार्पण समारोह में पु पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, ट्रायबल वेलफेयर फेयर कमेटी के चेयरमैन राजीव वरधे, शालिनीताई मेधे हॉस्पिटल नागपुर के डॉ. अश्विन रडके, नागपुर के समाज कल्याण अधिकारी अजय ठाकरे, माऊली सेवा मित्र मंडल के अध्यक्ष सुहास खरे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नक्सल सेल के पुलिस निरीक्षक श्रीकांत हत्तीमारे ने किया। आभार प्रदर्शन कल्याण शाखा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रामेश्वर पिपरेवार ने किया।

डिप्रेशन से युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

साकोली-रोजगार न मिलने से डिप्रेशन में आकर 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना साकोली तहसील के जमनापुर में घटी. मृतक का नाम फ्रेंड्स कॉलोनी जमनापुर निवासी साहिल वासुदेव पटोले (26) है. साहिल ने पॉलिटेक्निक से स्नातक किया था. वह तब नौकरी की तलाश में था. हालांकि, वह उदास था क्योंकि उसे नौकरी



नहीं मिल पा रही थी. इसी स्थिति में उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच पुलिस निरीक्षक आचरेकर तथा कर्मचारी कर रहे हैं